नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 103
दि. 14.01.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

ईरान उबलते ज्वालामुखी पर: सड़कों पर खून, सत्ता के सामने अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक संकट

(जीएनएस)। तेहरान। ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह और हिंसक दौर से गुजर रहा है। बीते दो हफ्तों से देश के कई शहरों में जारी व्यापक विरोध-प्रदर्शन अब खुली हिंसा में बदल चुके हैं। सरकारी स्वीकारोक्ति के मुताबिक अब तक करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के जवान दोनों शामिल हैं। हालांकि विपक्षी और निर्वासित ईरानी मीडिया इस आंकड़े को कहीं अधिक भयावह बताते हुए मृतकों की संख्या 12,000 से ज्यादा होने का दावा कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इतने बड़े पैमाने पर मौतों की बात स्वीकार की है, जिससे संकट की गंभीरता और गहराती नजर आ रही है।

एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने बताया कि हालिया हिंसा के लिए तथाकथित "आतंकवादी तत्व" जिम्मेदार हैं और इन्हीं के कारण हालात बेकाबू हुए। अधिकारी के अनुसार, मारे गए लोगों में सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान अपनी जान गंवाई। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मृतकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों का अनुपात क्या है। इस अस्पष्टता ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है।

यह अशांति ऐसे समय में भड़की है जब ईरान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा के अवमूल्यन और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल बना दिया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यह आंदोलन पिछले तीन वर्षों में सरकार के सामने खड़ी सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती माना जा रहा है। इसके साथ ही, बीते वर्ष इस्राइल और अमेरिका से जुड़े हमलों और अंतरराष्ट्रीय दबावों ने ईरान की स्थिति को और नाजुक बना दिया है।

ईरान की सत्ता, जो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से लगातार शासन में है, इस संकट से निपटने के लिए दोहरी रणनीति अपनाए हुए है। एक ओर सरकार यह स्वीकार कर रही है कि आर्थिक परेशानियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा जायज है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर उतरने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। सरकारी बयानबाजी में अमेरिका और इस्राइल पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शनों पर अब "आतंकवादी समूहों" का कब्जा हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की पुरानी रणनीति है, जिसके तहत आंतरिक असंतोष को विदेशी साजिश बताकर कुचला जाता है।

बीते दिनों रात के अंधेरे में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें गोलीबारी, जलते वाहन और आग की लपटों में घिरी इमारतें साफ देखी जा सकती हैं। इन वीडियो में से कुछ की पुष्टि अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने भी की है। हालांकि सरकार ने इंटरनेट सेवाएं और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी है, जिससे सूचनाओं का प्रवाह बाधित हुआ है और वास्तविक हालात का आकलन करना मुश्किल हो गया है।

मानवाधिकार संगठनों ने पहले ही सैकड़ों मौतों की पुष्टि करते हुए यह दावा किया था कि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी हालात पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा बेहद चिंताजनक है और यह भयावह चक्र अब रुकना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईरानी जनता की निष्पक्षता, समानता और न्याय की मांगों को सुना जाना जरूरी है।

तुर्क ने यह भी चेतावनी दी कि गिरफ्तार किए गए हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन होगा। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कहीं विरोध-प्रदर्शनों का दुरुपयोग कर हालात को और भड़काया न जाए, क्योंकि इससे आम नागरिकों की जान को और खतरा पैदा हो सकता है।

इस बीच, निर्वासित ईरानी मीडिया ईरान इंटरनेशनल ने एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। वेबसाइट के अनुसार, तेहरान समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा मौतें 8 और 9 जनवरी को हुईं, जब इंटरनेट और बिजली पूरी तरह बंद कर दी गई थी। इस रिपोर्ट ने इन घटनाओं को "ईरान के समकालीन इतिहास में सबसे बड़ी हत्या" करार दिया है। दावा किया गया है कि यह आंकड़ा सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े सूत्रों, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न प्रांतों, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, मृतकों के परिजनों और चिकित्सा कर्मियों की जानकारी पर आधारित है।

सरकार और विपक्षी मीडिया के आंकड़ों में भारी अंतर ने स्थिति को और रहस्यमय बना दिया है। एक ओर सरकारी आंकड़े 2,000 मौतों की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्ष 12,000 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा कर रहा है। सच चाहे जो भी हो, इतना तय है कि ईरान इस समय खून, गुस्से और भय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि क्या सरकार संवाद और सुधार का रास्ता अपनाएगी या दमन की नीति ईरान को और गहरे संकट में धकेल देगी।

मतदाता सूची पर घमासान: ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, लोकतंत्र पर संकट का दावा

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच तीखा टकराव सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि राज्य में मतदाता सूची के मसौदे से एकतरफा तरीके से 54 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। नबान्ना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। मुख्यमंत्री के अनुसार, जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें बड़ी संख्या ऐसे वास्तविक मतदाताओं की है, जिन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की यह प्रक्रिया न केवल असंवेदनशील है, बल्कि संदेह के घेरे में भी है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं को इस प्रक्रिया में निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, नाम में मामूली बदलाव या वर्तनी के अंतर को आधार बनाकर मताधिकार छीन लेना

पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं ने समाज में अपनी पहचान बदलने के लिए संघर्ष किया है और अब उन्हें मतदाता सूची से बाहर कर देना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी कवायद दिल्ली में बैठकर की गई और इसमें आधुनिक तकनीक, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल्स का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तथाकथित 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' यानी तार्किक विसंगति का तर्क बाद में जोड़ा गया, ताकि बड़े पैमाने पर नाम हटाने को वैध ठहराया जा सके। ममता बनर्जी का कहना है कि मतदाता सूची की शुद्धता के नाम पर अपनाई गई यह पद्धति पारदर्शी नहीं है और इससे आम लोगों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया से उठ सकता है।

मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को राज्य के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनका दावा है कि आने वाले समय में अंतिम मतदाता सूची से एक करोड़ और नाम हटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ, तो यह पश्चिम बंगाल के लाखों नागरिकों के मताधिकार को छीनने जैसा होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष और संवैधानिक होना चाहिए, न कि किसी एजेंडे के तहत काम करना। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है और जनता के मन में संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेगी। उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ी तो कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर लड़ाई लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी ने आम लोगों से भी अपील की कि वे अपने मतदाता अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएं। उनका कहना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से नहीं चलता, बल्कि हर नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा से चलता है।

इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे केंद्र और संवैधानिक संस्थाओं की मिलीभगत बताकर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि विपक्षी दलों की ओर से अभी तक इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची का मुद्दा पश्चिम बंगाल में एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक विवाद बन सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या सफाई देता है और क्या इस विवाद का कोई समाधान निकल पाता है या यह टकराव और गहराता जाएगा।

भ्रष्टाचार जांच पर सुप्रीम कोर्ट की दो राय, अफसरों पर कार्रवाई से पहले मंजूरी के सवाल पर कानून अधर में

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने से पहले पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम लेकिन खंडित फैसला सुनाया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत की पीठ इस मुद्दे पर किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि दोनों न्यायाधीशों की राय अलग-अलग रही। इसके चलते अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष रखा जाएगा, ताकि बड़ी पीठ का गठन कर इस संवेदनशील संवैधानिक प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी लड़ाई की दिशा तय करेगा, बल्कि प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही और संरक्षण के संतुलन को लेकर भी दूरगामी प्रभाव डालेगा। विवाद का केंद्र वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में किया गया संशोधन है, जिसके तहत धारा 17ए को कानून में शामिल किया गया। इस धारा के अनुसार, किसी लोकसेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दी गई सिफारिशों या लिए गए फैसलों के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच या पूछताछ शुरू नहीं की जा सकती। सरकार का तर्क रहा है कि यह प्रावधान ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण शिकायतों और राजनीतिक या निजी प्रतिशोध से बचाने के लिए लाया गया है। वहीं, इसके आलोचकों का कहना है कि यही प्रावधान भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक मजबूत ढाल बन गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में दलील दी कि धारा 17ए भ्रष्टाचार विरोधी कानून की आत्मा को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि चूंकि पूर्व मंजूरी देने का अधिकार सरकार या उसके अधीन प्राधिकरण के पास होता है, इसलिए अक्सर राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से अनुमति नहीं दी जाती। इसका नतीजा यह होता है कि गंभीर आरोपों के बावजूद जांच शुरू ही नहीं हो पाती और भ्रष्टाचार के मामले दबे रह जाते हैं। उनके अनुसार, यह प्रावधान कानून के उस उद्देश्य के खिलाफ है, जिसके तहत लोकसेवकों को जवाबदेह बनाया जाना था।

सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल विश्वनाथन (जस्टिस विश्वनाथन) ने अपने-अपने फैसले लिखे, लेकिन दोनों की राय एक-दूसरे से बिल्कुल उलट रही। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि किसी लोकसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से पहले पूर्व मंजूरी की शर्त भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मूल उद्देश्य के विपरीत है। उनके अनुसार, यह प्रावधान जांच प्रक्रिया को रोकता है और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देता है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध में जांच शुरू करने के लिए किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने धारा 17ए को असंवैधानिक बताते हुए इसे समाप्त किए जाने की जरूरत जताई और कहा कि कानून को ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जांच एजेंसियों के हाथ बांध दे।

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि धारा 17ए को पूरी तरह खत्म करना ऐसा होगा, जैसे "बच्चे को नहलाने के पानी के साथ ही बाहर फेंक देना"। उनके अनुसार, यह प्रावधान प्रशासनिक तंत्र में ईमानदार अधिकारियों के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच है। उन्होंने तर्क दिया कि बिना किसी प्रारंभिक छानबीन या अनुमति के जांच शुरू करने की छूट देने से अफसरशाही भय के माहौल में काम करेगी और निर्णय लेने से कतराने लगेगी। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने धारा 17ए को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, हालांकि उन्होंने यह शर्त जोड़ी कि पूर्व मंजूरी का निर्णय लोकपाल या राज्य स्तर पर लोकायुक्त द्वारा किया जाना चाहिए, न कि केवल सरकार द्वारा।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन के अनुसार, यह व्यवस्था एक संतुलन बनाती है, जिसमें एक ओर ईमानदार अधिकारियों को बेवजह की परेशानियों से बचाया जा सके और दूसरी ओर भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सुरक्षा के बिना प्रशासनिक तंत्र में काम करने वाले सक्षम और प्रतिभाशाली लोग सार्वजनिक सेवा से दूर हो सकते हैं, जिससे शासन व्यवस्था कमजोर पड़ेगी।

दोनों न्यायाधीशों की परस्पर विरोधी राय के चलते सुप्रीम कोर्ट किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। इसी कारण अदालत ने निर्देश दिया कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए, ताकि बड़ी पीठ का गठन कर इस संवैधानिक प्रश्न का निर्णायक उत्तर दिया जा सके। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब देश में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जनता की संवेदनशीलता बढ़ी हुई है और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं।

विधवा बहू को भी मिलेगा ससुराल की संपत्ति से भरण-पोषण, सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों की नई व्याख्या की

(जीएनएस)। नई दिल्ली। विधवा महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत विधवा बहू को अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है, भले ही उसके पति की मृत्यु ससुर के जीवनकाल में हुई हो या बाद में। अदालत ने कहा कि कानून की मंशा परिवार की निर्भर महिलाओं को संरक्षण देने की है और इसकी व्याख्या संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती।

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में दायर सभी दीवानी अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 21 के तहत "आश्रित" की परिभाषा में विधवा बहू को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अदालत ने कहा कि यदि विधवा बहू स्वयं के भरण-पोषण में असमर्थ है और उसके पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है, तो वह अपने ससुर की संपत्ति से मेंटिनेंस का दावा कर सकती है। यह अधिकार केवल नैतिक नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक संरचना और पारिवारिक व्यवस्था में विधवा बहू अक्सर सबसे अधिक असुरक्षित स्थिति में होती है। ऐसे में कानून का उद्देश्य उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देना है। अदालत ने कहा कि पति की मृत्यु की समय-सीमा को आधार बनाकर विधवा बहू के अधिकार को सीमित करना न केवल कानून की भावना के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

यह मामला डॉ. महेंद्र प्रसाद के परिवार से जुड़ा था, जिनका दिसंबर 2021 में निधन हो गया था। उनकी बहू गीता शर्मा ने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग की थी। गीता शर्मा के पति की मृत्यु वर्ष 2023 में हुई थी। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए मेंटिनेंस देने से इनकार कर दिया था कि ससुर की मृत्यु के समय उनका बेटा जीवित था, इसलिए बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण का अधिकार नहीं बनता। फैमिली कोर्ट के इस फैसले ने कानून की व्याख्या को केवल तकनीकी आधार तक सीमित कर दिया था।

हालांकि, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि विधवा बहू की वास्तविक जरूरतों और उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भरण-पोषण तय किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया था कि वह गीता शर्मा की आवश्यकताओं के अनुरूप मेंटिनेंस निर्धारित करे। इस आदेश को डॉ. महेंद्र प्रसाद के अन्य वारिसों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में डॉ. प्रसाद के दूसरे बेटे की विधवा बहू और एक महिला भी शामिल थी, जो लंबे समय तक उनके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का दावा कर रही थी। इन सभी ने तर्क दिया कि गीता शर्मा को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण देने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि ससुर की मृत्यु के समय उनका बेटा जीवित था। लेकिन शीर्ष अदालत ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम का उद्देश्य परिवार के उन सदस्यों की रक्षा करना है, जो आर्थिक रूप से निर्भर हैं। धारा 21 (VII) में विधवा बहू को स्पष्ट रूप से आश्रित के रूप में शामिल किया गया है और इस प्रावधान की अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता, जिससे वह अपने मूल उद्देश्य को ही निष्फल कर दे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बेंगलुरु में लोकतंत्र की वापसी, 30 जून से पहले होंगे पांचों नगर निगमों के चुनाव

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से टलते आ रहे बेंगलुरु के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह सम्मान करेगी और ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले सभी पांच नगर निगमों के चुनाव 30 जून से पहले कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी कीमत पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं करेगी। डीके शिवकुमार ने यह बयान ऐसे समय दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश देते हुए तय समयसीमा के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने को कहा है। अदालत ने लंबे समय से निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना चल रहे बेंगलुरु नगर प्रशासन पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में इस तरह की देरी स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से यह पहला स्पष्ट राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, जिससे चुनाव की दिशा में ठोस कदम उठने की उम्मीद बढ़ गई है। उपमुख्यमंत्री ने आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस के आत्मविश्वास का भी खुलकर इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु की जनता ने कांग्रेस सरकार के कामकाज को करीब से देखा है और विकास, बुनियादी सुविधाओं तथा शहरी प्रशासन के मोर्चे पर पार्टी की नीतियों पर भरोसा जताएगी। शिवकुमार ने कहा कि शहर की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता कांग्रेस के पास है और यही भरोसा चुनावी नतीजों में भी नजर आएगा।

गौरतलब है कि बेंगलुरु में स्थानीय निकाय का पिछला निर्वाचित कार्यकाल सितंबर 2020 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से ही शहर का प्रशासन प्रशासकों के भरोसे चल रहा है। लगभग चार वर्षों तक निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना देश की आईटी राजधानी का संचालन होना लगातार आलोचना का विषय रहा है। नागरिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने कई बार इस देरी पर सवाल उठाए और इसे शहरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। इस बीच सितंबर 2025 में राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी को भंग कर दिया था। इसके स्थान पर ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसके तहत शहर को पांच नए नगर निगमों—मध्य, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण—में विभाजित किया गया। सरकार का तर्क था कि बेंगलुरु जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते महानगर के बेहतर प्रशासन के लिए यह संरचनात्मक बदलाव जरूरी है, ताकि सेवाओं की डिलीवरी अधिक प्रभावी हो सके और स्थानीय समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके।

अब इन पांचों नए नगर निगमों में पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। यह चुनाव केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बेंगलुरु की शहरी राजनीति के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नए निगमों के गठन से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ ही यह भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी, क्योंकि मतदाताओं को नई संरचना और सीमाओं के अनुरूप खुद को ढालना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये चुनाव कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के लिए भी बेहद अहम हैं। बेंगलुरु राज्य की आर्थिक धुरी है और यहां का जनमत राज्य की राजनीति पर दूरगामी असर डालता है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

दुर्घटना उन्मुख क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप हो

देश में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार और समाज के स्तर पर चिंताएं तो व्यक्त की जाती हैं लेकिन इन्हें रोकने के लिये कारगर उपाय सिरे चढ़ते नजर नहीं आते। इस बारे में बार-बार वायदे किए जाते हैं, वहीं सुधार के लिये टुकड़ों-टुकड़ों में हस्तक्षेप किया जाता है। फलतः परिणाम वही ढाक के तीन पात रहता है। यह आंकड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में हर साल 1.6 लाख से अधिक मौतें सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं। विडंबना देखिए कि किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के मुकाबले सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा लोगों की जान ले लेती हैं। हाल ही में सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के लिये किए गए सर्वेक्षण में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। संस्था द्वारा वर्ष 2023 व 2024 में 100 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं पर किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि शाम छह बजे से रात नौ बजे तक समय सड़क हादसों के लिये सबसे घातक होता है। इसके अलावा दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिये 18 सड़क गलियारों की पहचान की गई है, जिनमें सर्वेक्षण अवधि में सबसे अधिक मौते हुई थीं। इसके साथ ही दुर्घटना की दृष्टि से संवेदनशील सौ जिलों में ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य पहल है। यह जानते हुए कि दुर्घटना रोकने के लिये सामान्य सलाह और एक समान नीतियां लक्ष्य हासिल करने में विफल रही हैं। यकीनी तौर पर दुर्घटना उन्मुख क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप बदलाव लाने के लिये बेहतर दृष्टिकोण साबित हो सकता है। बहुत संभव है कि एक खराब ढंग से डिजाइन किया गया मोड़, सड़क पर पर्याप्त रोशनी का न होना, प्रवर्तन में शिथिलता तथा ड्राइविंग में लापरवाही की आदतें, किसी क्षेत्र या जिला विशेष में सड़क दुर्घटनाओं की वजह हो सकती है। निश्चित तौर पर उच्च मृत्यु दर वाले गलियारों का मानचित्रण अधिकारियों को, उन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सुधार, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया बल तैनात करने में सहायक हो सकता है।

निस्संदेह, साक्ष्य और अतीत के अनुभव बताते हैं कि लक्षित प्रवर्तन बेहतर परिणाम दे सकता है। बंगलुरू का अनुभव बताता है कि लक्षित प्रयासों से वहां लगातार दूसरे वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के बावजूद मृत्यु दर में कमी आई है। जो इन प्रयासों की सार्थकता को दर्शाता है। निस्संदेह, अन्य शहरों को भी डेटा आधारित पुलसिंग, सीसीटीवी निगरानी और यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिये इस मॉडल को अपनाना होगा। इसमें दो राय नहीं कि केंद्र सरकार की योजना तभी सफल होगी, जब वह पहचान और प्रतीकात्मकता से आगे बढ़कर काम करे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी पिछली कोशिशें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल न होने से विफल रही हैं। इन सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये निरंतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कार्यान्वयन एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के साथ ही परिणामों का नियमित ऑडिट करना आवश्यक है। इस बाबत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों को कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिए। वैसे सिर्फ राजमार्गों पर ही ध्यान केंद्रित करने के भी कई खतरे हैं। यह जानते हुए कि देश में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क नेटवर्क का मुश्किल से 2 से तीन प्रतिशत हिस्सा ही है। लेकिन ट्रैफिक की गति की तीव्रता के चलते इन पर होने वाली मौतों की संख्या कहीं ज्यादा है। साल 2025 की पहली छमाही ही में करीब छब्बीस हजार से अधिक मौतें हुई हैं। वास्तव में शहरी सड़कें, जहां पैदल यात्री,साइकिल चालक और दोपहिया वाहन चालकों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या का बड़ा हिस्सा है, वे अक्सर उपेक्षित रह जाती हैं। इन सड़कों को बेहतर बनाने के लिये निवेश बढ़ाए जाने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षित डिजाइन तैयार करने, वाहनों की गति का प्रबंधन करने, हेलमेट और सीट बेल्ट बांधना सुनिश्चित करने तथा आपातकालीन देखभाल व्यवस्था को साथ-साथ लागू करने की भी आवश्यकता है।

कोशिकाओं से चिप पर बन रहे हैं मानव अंग

> इंग्लैंड के फ्रांसिस क्रिक इंस्टिट्यूट और स्विस कंपनी, एल्वियोलिक्स के शोधकर्ताओं ने सिर्फ एक व्यक्ति से ली गई स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल करके चिप पर मानव फेफड़े का पहला मॉडल विकसित किया है। ये चिप एक व्यक्ति में सांस लेने की गति और फेफड़ों की बीमारी को उत्पन्न करते हैं, जिससे टीबी जैसे संक्रमण के इलाज का परीक्षण करने और व्यक्ति विशेष दवा देने की उम्मीद जगी है।

मनुष्य के रोगों को बेहतर ढंग से समझने और उनका प्रभावी उपचार खोजने के लिए वैज्ञानिक निरंतर नए तरीके विकसित कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इंसानी कोशिकाओं से चिप पर शरीर के अंग उगा रहे हैं जबकि कुछ रिसर्चर अंगों के डिजिटल संस्करण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इंग्लैंड के फ्रांसिस क्रिक इंस्टिट्यूट और स्विस कंपनी, एल्वियोलिक्स के शोधकर्ताओं ने सिर्फ एक व्यक्ति से ली गई स्टेम कोशिकाओं का इस्तेमाल करके चिप पर मानव फेफड़े का पहला मॉडल (लंग-ऑन-चिप) विकसित किया है। ये चिप एक व्यक्ति में सांस लेने की गति और फेफड़ों की बीमारी को उत्पन्न करते हैं, जिससे टीबी जैसे संक्रमण के इलाज का परीक्षण करने और व्यक्ति विशेष दवा देने की उम्मीद जगी है।

दरअसल, फेफड़ों में एल्वियोली नामक हवा की थैली गैस के आदान-प्रदान के लिए आवश्यक जगह होती है और साथ ही यह थैली सांस से अंदर जाने वाले वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ अवरोधक का भी काम करती है। ये रोगाणु फ्लू या टीबी जैसी सांस की बीमारियां पैदा करते हैं। शोधकर्ता चिप पर फेफड़े बनाकर प्रयोगशाला में मानव कोशिकाओं और बैक्टीरिया के बीच होने वाले द्वंद्व को पुनर्निर्मित कर रहे हैं। प्लास्टिक की इस चिप पर मानव फेफड़ों की छोटी इकाइयां हैं जिनमें छोटी-छोटी नलियां और कम्पार्टमेंट होते हैं। इस मामले में, उनका मकसद हवा की थैलियों को फिर से बनाना था ताकि यह समझा जा सके कि वे संक्रमण पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। अभी तक ये लंग ऑन-चिप डिवाइस मरीज से ली गई कोशिकाओं और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कोशिकाओं के मिश्रण से बनाए जाते थे। इस तरह के चिप किसी एक व्यक्ति के फेफड़ों के काम या बीमारी की प्रगति को पूरी तरह से दोहरा नहीं सकते थे।

इस अध्ययन में क्रिक की टीम ने चिप पर फेफड़े का एक नया मॉडल विकसित किया है, जिसमें सिर्फ एक डोनर की स्टेम कोशिकाओं से ली गई आनुवंशिक रूप से एक जैसी कोशिकाएं होती हैं। प्रयोगशाला द्वारा पहले विकसित की गई एक विधि के आधार पर शोधकर्ताओं ने प्लोरिपोटेंट (बहुक्षमता) स्टेम कोशिकाओं से 'एल्वियोलर एपिथेलियल' कोशिकाएं और 'वैस्कुलर एंडोथेलियल' कोशिकाएं बनाईं। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो शरीर में किसी भी कोशिका में विकसित हो सकती हैं। इन एपिथेलियल और एंडोथेलियल कोशिकाओं को एक बहुत पतली झिल्ली के ऊपर और नीचे अलग-अलग उगाया जाता है ताकि हवा की थैली के अवरोध को पुनर्निर्मित किया जा सके। इसके बाद, वैज्ञानिकों ने चिप में मैक्रोफेज नामक इम्यून कोशिकाएं डालीं, जिन्हें उसी डोनर की स्टेम कोशिकाओं से बनाया गया था। चिप में बीमारी के शुरुआती चरण निर्मित करने के लिए उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया डाले। टीबी से संक्रमित चिप में टीम ने बड़े मैक्रोफेज समूह देखे। संक्रमण के पांच दिन बाद, एंडोथेलियल और एपिथेलियल कोशिकाओं के अवरोध टूट गए, जिससे पता चला कि हवा की थैली का फंक्शन खराब हो गया था। इस अध्ययन के वरिष्ठ लेखक मैक्स गुटिरेज ने कहा कि आज ऐसी तकनीकों की मांग बढ़ रही है जिनमें जानवरों के अंगों का प्रयोग नहीं होता। ऑर्गन-ऑन-चिप जैसे तरीके प्रयोगशाला में इंसानी सिस्टम को फिर से बनाने के लिए जरूरी होते जा रहे हैं क्योंकि जानवरों और इंसानों के बीच फेफड़ों की संरचना, इम्यून कोशिकाओं की बनावट और बीमारी के विकास में अंतर होता है। नई चिप से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि टीबी जैसे संक्रमण किसी व्यक्ति पर कैसे असर डालेंगे। साथ ही यह टेस्ट भी किया जा सकेगा कि एंटीबायोटिक्स जैसे उपचार कितने प्रभावी हैं। वैज्ञानिकों के अन्य दल ने चूहे के मस्तिष्क के कॉर्टेक्स का डिजिटल संस्करण बनाया है। हमारा मस्तिष्क ऊपर से अखरोट की गिरी जैसा दिखता है। इसकी उभरी हुई सिलवटों वाली सतह को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। ज्ञान और स्मृति जैसे अनेक उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य मस्तिष्क के कॉर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। दुनिया के वैज्ञानिक कॉर्टेक्स की गहन जांच करके मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना चाहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं के एक दल ने जापान के शक्तिशाली फुगाकू सुपरकम्प्यूटर का उपयोग करके चूहे के मस्तिष्क के कॉर्टेक्स का एक डिजिटल मॉडल बनाया है, जो अब तक बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे वास्तविक मॉडल है। डिजिटल मस्तिष्क एक वास्तविक मस्तिष्क की तरह व्यवहार करता है, जिससे वैज्ञानिक रोग की प्रगति, तंत्रिका गतिशीलता और संभावित उपचारों का अध्ययन कर सकते हैं। जैविक डेटा सेट को शक्तिशाली मॉडलिंग सॉफ़्टवेयर के साथ जोड़कर अंतरराष्ट्रीय टीम ने साबित कर दिया है कि बड़े पैमाने पर जैवभौतिक रूप से सटीक मस्तिष्क मॉडल बनाना अब संभव है। चूहे के कॉर्टेक्स का यह पूरी तरह से डिजिटल संस्करण है। यह वैज्ञानिकों को एक आभासी वातावरण में अल्जाइमर या मिर्गी जैसी स्थितियों का पुनर्निर्माण करके मस्तिष्क के काम करने के तरीके का पता लगाने की एक नई विधि प्रदान करता है। वे देख सकते हैं कि क्षति तंत्रिका नेटवर्क के माध्यम से कैसे आगे बढ़ती है। इस मॉडल से अनुभूति और चेतना से संबंधित प्रक्रियाओं की भी जांच की जा सकती है। यह मॉडल संरचना और गतिविधि दोनों को दर्शाता है, जिसमें लगभग एक करोड़ स्नायु कोशिकाएं (न्यूरॉन्स), 26 अरब स्नायु कनेक्शन (सिनेप्स) और 86 जुड़े हुए मस्तिष्क क्षेत्र शामिल हैं।

यह उपलब्धि फुगाकू सुपरकम्प्यूटर की वजह से संभव हुई है, जो जापान का प्रमुख सिस्टम है। यह दुनिया के सबसे तेज सुपर कम्प्यूटरों में गिना जाता है। यह सिस्टम प्रति सेकंड अरबों गणनाएं करने में सक्षम है। अमेरिका के एलन इंस्टिट्यूट के शोधकर्ताओं ने जापान की इलेक्ट्रो-कम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी और तीन अन्य जापानी संस्थानों की टीमों के साथ मिलकर इस परियोजना को साकार किया।

विज्ञानी अब कॉर्टेक्स के इस मॉडल का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि बीमारियां कैसे विकसित होती हैं, मस्तिष्क तरंगें ध्यान को कैसे प्रभावित करती हैं, या दौरे मस्तिष्क में कैसे फैलते हैं। पहले, इस तरह के अध्ययनों के लिए वास्तविक जैविक ऊतक की आवश्यकता होती थी और एक समय में केवल एक ही प्रयोग किया जा सकता था। अब शोधकर्ता आभासी स्थान में कई तरह के आइडिया की जांच कर सकते हैं। ये मॉडल लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही तंत्रिका संबंधी विकारों के शुरुआती लक्षणों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं और वैज्ञानिकों को डिजिटल सेटिंग में संभावित उपचारों या चिकित्सा पद्धतियों का मूल्यांकन करने में सक्षम बना सकते हैं।

एलन इंस्टिट्यूट के शोधकर्ता, एंटोन आर्किपोव का कहना है कि हम पर्याप्त कम्प्यूटिंग शक्ति के साथ इस प्रकार के मस्तिष्क मॉडल को प्रभावी ढंग से चला सकते हैं। यह हमें विश्वास दिलाता है कि बहुत बड़े मॉडल न केवल संभव हैं, बल्कि सटीकता के साथ हासिल करने योग्य भी हैं। वैज्ञानिकों का यह प्रयास तंत्रिका विज्ञान और उन्नत कम्प्यूटिंग क्षमताओं को एक मंच पर लाया है। चूहे के डिजिटल कॉर्टेक्स को देखना वास्तविक समय में जीव विज्ञान को देखने जैसा है। वैज्ञानिकों का दीर्घकालिक लक्ष्य संपूर्ण-मस्तिष्क मॉडल बनाना है, जिसमें मानव मस्तिष्क भी शामिल है।

प्रेरणा

दर्द से टकराकर गढ़ा गया क्रांतिकारी चरित्र

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास केवल संघर्षों और बलिदानों की सूची नहीं है, बल्कि यह उन असाधारण व्यक्तित्वों की आंतरिक यात्राओं का भी दस्तावेज है, जिन्होंने अपने विचारों और संकल्प को सिद्ध करने के लिए स्वयं को कठोरतम परीक्षाओं से गुजारा। अमर शहीद सुखदेव का जीवन ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसमें क्रांति केवल बाहरी शत्रु से टकराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह आत्म-अनुशासन, सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता की चरम अवस्था तक पहुंची। सुखदेव का व्यक्तित्व इस बात का प्रमाण है कि सच्चा क्रांतिकारी पहले अपने भीतर के भय और पीड़ा को पराजित करता है, उसके बाद ही वह सत्ता और अन्याय से लड़ने के योग्य बनता है।

सुखदेव जिस संगठन से जुड़े थे, उसका नाम 'विलेजर' था। यह नाम अपने आप में उनके दृष्टिकोण को उजागर करता है। वे मानते थे कि आजादी की लड़ाई केवल शहरों, शिक्षित वर्ग या कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांवों और आम जनता तक उसकी जड़ें फैलनी चाहिए। सुखदेव अपने साथियों के बीच अपने हठ और अडिग स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जो निर्णय उन्होंने ले लिया, उसे बदलना लगभग असंभव था। यह हठ जिद नहीं, बल्कि लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण का रूप था, जो आगे चलकर उनके जीवन के एक अत्यंत असाधारण प्रसंग में प्रकट हुआ।

विद्यार्थी जीवन में सुखदेव ने अपने बाएं हाथ पर 'ओउम' और अपना नाम गुदवा लिया था। उस समय यह उनके आत्मविश्वास, आस्था और पहचान का प्रतीक रहा होगा। लेकिन जब क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और उन्हें भूमिगत होकर फरारी का जीवन जीना पड़ा, तब यही निशान उनके लिए खतरे का कारण बन गया। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों की पहचान के लिए किसी भी छोटे से संकेत को पकड़ने की कोशिश करती थी। सुखदेव यह भली-भांति समझते थे कि यदि कभी गिरफ्तारी हुई तो यह निशान उनकी पहचान तुरंत उजागर कर देगा। इस समस्या का समाधान उन्होंने जिस तरीके से किया, वह सामान्य बुद्धि और साहस की सीमाओं से बहुत आगे था।

आगरा में क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान बम निर्माण के लिए नाइट्रिक एसिड खरीदा गया था। सुखदेव जानते थे कि यह एसिड कितना खतरनाक होता है और शरीर पर गिरते ही किस प्रकार भयानक जलन और घाव पैदा करता है। फिर भी उन्होंने बिना किसी साथी को बताए अपनी सहनशक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बहुत-सा नाइट्रिक एसिड अपने बाएं हाथ पर बने 'ओउम' और अपने नाम पर डाल दिया। यह निर्णय केवल पहचान मिटाने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह जानने की एक कठोर साधना भी थी कि मनुष्य पीड़ा की कितनी गहराई तक जा सकता है और वहां भी अपना संतुलन बनाए रख सकता है।

कुछ ही समय में एसिड का असर दिखाई देने लगा। जिस स्थान पर एसिड डाला गया था, वहां गहरे घाव उभर आए। त्वचा जलने लगी, पूरा हाथ बुरी तरह सूज गया और असहनीय पीड़ा ने पूरे शरीर को जकड़ लिया। शाम होते-होते तेज बुखार भी चढ़ आया। यह स्थिति किसी भी सामान्य व्यक्ति को चीखने-चिल्लाने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन सुखदेव ने अपनी पीड़ा को पूरी तरह अपने भीतर समेट लिया। उन्होंने न तो किसी से मदद मांगी और न ही अपने दर्द का कोई संकेत दिया। वे सामान्य दिनचर्या की तरह अपने काम में लगे रहे, मानो शरीर पर कुछ हुआ ही न हो।

तीन दिन तक वे इसी अवस्था में रहे। भीतर जलता हुआ दर्द, सूजन और बुखार उनके शरीर को कमजोर कर रहा था, लेकिन उनका मन अडिग था। तीसरे दिन जब उन्होंने नहाने के लिए कमीज उतारी, तब भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद की नजर उनके जख्मों पर पड़ी। दोनों यह देखकर स्तब्ध रह गए। ऐसे गहरे और भयानक घाव किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि जानबूझकर झेली गई पीड़ा का परिणाम थे। उन्हें इस बात पर गहरा आक्रोश हुआ कि सुखदेव ने इतनी बड़ी बात छिपाकर रखी। उनकी नाराजगी में चिंता, स्नेह और जिम्मेदारी का भाव साफ झलक रहा था।

सुखदेव ने उनकी प्रतिक्रिया को मुस्कान के साथ स्वीकार किया। हंसते हुए उन्होंने कहा कि अब पहचान भी मिट जाएगी और यह भी समझ आ गया कि एसिड में कितनी जलन होती है। यह वाक्य केवल हल्का-फुल्का उत्तर नहीं था, बल्कि उनके जीवन दर्शन का सार था। वे हर पीड़ा को अनुभव और तैयारी के रूप में देखते थे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति दर्द से डर जाता है, वह बड़े उद्देश्य के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित नहीं कर सकता। उनके लिए यह परीक्षा भविष्य के और भी कठिन संघर्षों की तैयारी थी।

इसके बाद भी सुखदेव उसी हालत में आगरा में चार-पांच दिन तक रहे। जख्म खुले थे, हाथ सूजा हुआ था और शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। सभी साथियों ने उनसे बार-बार आग्रह किया कि वे दवा लें, मलहम लगवाएं और पट्टी कराएं, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। उनका विश्वास था कि क्रांति के रास्ते में व्यक्तिगत कष्टों को प्राथमिकता देना लक्ष्य से भटकने जैसा है। वे बैठकों में शामिल होते रहे, योजनाओं पर चर्चा करते रहे और आंदोलन की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते रहे।

अंततः बिना किसी इलाज के वे अगले मिशन के लिए लाहौर रवाना हो गए। यह घटना सुखदेव के व्यक्तित्व को केवल एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक तपस्वी योद्धा के रूप में स्थापित करती है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आजादी की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि उसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक साथ तपाना पड़ता है। सुखदेव का यह प्रसंग आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने उद्देश्य के लिए इतनी पीड़ा सहने का साहस रखते हैं। उनका जीवन इस सत्य का सजीव प्रमाण है कि इतिहास वही बदलता है, जो दर्द से भागता नहीं, बल्कि उसे साधना बना लेता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के War Room में क्या चल रहा है? किन देशों के नाम लाल घेरे में हैं?

आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के वार रूम में इस समय क्या चल रहा है। व्हाइट हाउस के भीतर कौन से देश के नक्शे खुले हैं, किन देशों के नाम लाल घेरे में हैं और किन मोर्चों पर सैन्य और आर्थिक हमले की तैयारी हो रही है। देखा जाये तो अमेरिकी राष्ट्रपति के सार्वजनिक बयानों, नीतिगत संकेतों और सैन्य गतिविधियों से साफ झलकता है कि अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। आइये आज इसी पर बात करते हैं और आपको तथ्यों के साथ पूरी जानकारी देते हैं कि ट्रंप के निशाने पर इस समय कौन कौन से देश हैं और उनके खिलाफ अमेरिका किस स्तर की तैयारी कर रहा है। देखा जाये तो साल 2026 की शुरुआत वैश्विक राजनीति के लिए एक बेचैन करने वाला संकेत लेकर आई है। दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक बार फिर उस भूमिका में दिख रहा है जिसे वह शीत युद्ध के दौर में निभाता था यानी निर्णायक दबाव डालने वाला सर्वशक्तिमान केंद्र। इस बार मंच पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी भाषा पहले से अधिक तीखी, अधिक उकसाने वाली और अधिक विस्फोटक बनी हुई है।

सबसे पहले वेनेजुएला की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रंप ने खुद को सार्वजनिक रूप से वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मर्यादा को जानबूझकर तोड़ा है। इसका सीधा संदेश यह है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को एक संप्रभु राष्ट्र की तरह नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र के एक प्रशासित इलाके की तरह देख रहा है। देखा जाये तो वेनेजुएला का सामरिक महत्व केवल राजनीतिक नहीं बल्कि ऊर्जा पर आधारित है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर नियंत्रण का अर्थ है वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव। ट्रंप का खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताना दरअसल यह बताने का तरीका है कि अमेरिका वहां सत्ता परिवर्तन को अब छिपाकर नहीं बल्कि खुले तौर पर संचालित करना चाहता है। यह सीधे तौर पर संसाधन नियंत्रण की राजनीति है। इसी कड़ी में क्यूबा को लेकर ट्रंप का रवैया भी ध्यान खींचता है। क्यूबा को तेल आपूर्ति रोकने की धमकी और उसके बाद यह कहना कि मार्को रुबियो का क्यूबा का राष्ट्रपति बनना उन्हें ठीक लगता है, यह सब मजाक नहीं है। यह एक राजनीतिक संदेश है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अब वैचारिक असहमति को सहन करने के मूड में नहीं है। वह खुले तौर पर यह संकेत दे रहा है कि जो सरकारें उसकी लाइन पर नहीं चलेंगी, उन्हें आर्थिक और राजनीतिक रूप से कुचल दिया जाएगा। देखा जाये तो मार्को रुबियो का नाम लेना प्रतीकात्मक है। एक ऐसा नेता जिसकी पहचान क्यूबा विरोधी राजनीति से जुड़ी रही है, उसे वहां के राष्ट्रपति पद से जोड़ना यह बताता है कि अमेरिका लोकतंत्र नहीं बल्कि अपने हितों के प्रति वफादार शासन चाहता है। यह बयान भले ही अनौपचारिक हो लेकिन इसके निहितार्थ बेहद गहरे हैं।

ईरान की बात करें तो आपको बता दें कि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका ईरान के लिए बहुत मजबूत सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। देखा जाये तो यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं है क्योंकि अमेरिका इस समय फारस की खाड़ी से लेकर पश्चिम एशिया तक अपनी सैन्य तैनाती मजबूत कर रहा है। हवाई हमलों से लेकर साइबर और ड्रोन हमलों तक की तैयारी की जा रही है। सवाल यह नहीं है कि हमला होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हमला कब और कितना बड़ा होगा?

देखा जाये तो यदि अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसके परिणाम केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। पूरा पश्चिम एशिया अस्थिर हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट सकती है। मुस्लिम देशों का रुख इस मामले में एक जैसा नहीं होगा। कुछ देश रणनीतिक मजबूरी में अमेरिका का सीमित समर्थन कर सकते हैं, लेकिन व्यापक इस्लामी दुनिया में इसका तीखा विरोध होगा। यह टकराव क्षेत्रीय से वैश्विक संकट में बदल सकता है। ईरान पर हमले का एक और परिणाम होगा प्रतिशोध। ईरान सीधे या परोक्ष रूप से अपने सहयोगी संगठनों के जरिये जवाब देगा। इसका असर इजरायल से लेकर खाड़ी देशों तक दिख सकता है। इस तरह यह संघर्ष किसी एक मोर्चे पर सीमित नहीं रहेगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की वैश्विक दादागिरी साफ दिखाई दे रही है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का यह कहना कि अमेरिका ने यदि उस क्षेत्र को नहीं लिया तो उसे चीन या रूस ले लेंगे, यह दर्शाता है कि अमेरिका दुनिया को अब भी एक शतरंज की बिसात मानता है जहां मोहरे उसकी मर्जी से हिलने चाहिए। यह मानसिकता बताती है कि बहुध्रुवीय दुनिया की सच्चाई को स्वीकार करने में अमेरिका अब भी असहज है। अब कोलंबिया की बात करें तो आपको बता दें कि कोलंबिया के राष्ट्रपति का ट्रंप से मिलने जाना एक दबाव भरी परिस्थिति में संवाद का प्रयास है। अमेरिकी धमकियों और दबाव ने कोलंबिया को बातचीत की मेज तक आने के लिए मजबूर किया है। यह अमेरिका की दबाव कूटनीति की सफलता भी है और उसकी सीमाओं का संकेत भी।

बहरहाल, जहां तक यह सवाल है कि दुनिया क्या एक और विश्व युद्ध की कगार पर है? इसका उत्तर भले अभी स्पष्ट नहीं हो लेकिन यह तो दिख ही रहा है कि फिलहाल दुनिया एक ऐसे दौर में जरूर है जहां टकराव की रेखाएं गहरी हो रही हैं। अमेरिका बनाम चीन, रूस, ईरान जैसे ध्रुव साफ दिख रहे हैं। अमेरिका की मौजूदा दादागिरी यह दिखाती है कि वह अपने पतन के डर से और अधिक आक्रामक होता जा रहा है।

अभियान

मां कामाख्या की कृपा से जीवन का रूपांतरण

भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शक्ति उपासना का स्थान अत्यंत विशिष्ट रहा है और इसी शक्ति परंपरा में मां कामाख्या का स्वरूप रहस्य, साधना और सृजन का अद्भुत संगम माना जाता है। मां कामाख्या केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह चेतना हैं जो इच्छा, संकल्प और सृजन की मूल ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहा जाता है कि जहां इच्छा जन्म लेती है, वहीं कामाख्या का वास होता है। इसलिए मां कामाख्या की उपासना को जीवन की समस्याओं का समाधान और मनोकामनाओं की पूर्ति का एक अत्यंत प्रभावी मार्ग माना गया है। असम की नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व में तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है और यह 51 शक्तिपीठों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है।

मां कामाख्या का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। अन्य देवी मंदिरों की तरह यहां मूर्ति नहीं, बल्कि योनि स्वरूप की पूजा होती है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन की निरंतरता और सृजन की शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि मां कामाख्या को इच्छाओं की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। मान्यता है कि जो भी साधक सच्चे मन, श्रद्धा और अनुशासन के साथ मां कामाख्या की साधना करता है, उसकी जीवन की उलझनें धीरे-धीरे सुलझने लगती हैं। चाहे समस्या धन की हो, प्रेम की हो, विवाह की हो, संतान की हो, स्वास्थ्य की हो या मानसिक अशांति की, मां कामाख्या की कृपा से जीवन में संतुलन और स्पष्टता आने लगती है।

तंत्र शास्त्र में मां कामाख्या को विशेष स्थान प्राप्त है। यहां की साधना केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह साधक के भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि मां कामाख्या की साधना करने से व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने लगता है। यही कारण है कि उनके मंत्रों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कामाख्या महामंत्र और बीज मंत्र साधक के भीतर सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं और जीवन की नकारात्मकता को धीरे-धीरे समाप्त करने लगते हैं।

कामाख्या का प्रणाम मंत्र अत्यंत सरल होते हुए भी गहन प्रभाव रखता है। "कामाख्ये कामसम्पन्ने कामेश्वरि हरप्रिये। कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरि नमोऽस्तु ते॥" यह मंत्र मां कामाख्या को साक्षात इच्छापूर्ति की शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। इस मंत्र का भावार्थ ही साधना का आधार है, जिसमें साधक अपनी कामनाओं को मां के चरणों में समर्पित कर देता है। वहीं बीज मंत्र "क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः" को अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। तंत्र परंपरा में 'क्लीं' बीज को आकर्षण, सृजन और चेतना जागरण का बीज कहा गया है। जब यह बीज मां कामाख्या के नाम के साथ जुड़ता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

मां कामाख्या के मंत्र जाप की विधि में अनुशासन और श्रद्धा का विशेष महत्व है। साधक को प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर शांत मन से पूजा स्थान पर बैठना चाहिए। मन में मां कामाख्या का स्मरण करते हुए उनसे कृपा और मार्गदर्शन की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद कम से कम तीन माला मंत्र जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि साधक लगातार 41 दिनों तक नियमपूर्वक इस मंत्र का जाप करता है, तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। कई साधकों का अनुभव रहा है कि इस अवधि के बाद मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होती है। मां कामाख्या के मंत्र जाप का सबसे बड़ा लाभ यह माना जाता है कि व्यक्ति के आकर्षण में स्वाभाविक वृद्धि होती है। यह आकर्षण केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। लोग स्वतः ही ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और टूटते हुए रिश्तों में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। कई साधकों का मानना है कि मां कामाख्या की कृपा से उनका प्रेम जीवन संतुलित और सफल हुआ है।

इसके साथ ही यह मंत्र रचनात्मकता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जो लोग अपने कार्यक्षेत्र में बार-बार असफलता, भ्रम या मानसिक थकान का अनुभव करते हैं, उनके लिए यह साधना अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। मंत्र जाप से मन की चंचलता कम होती है और विचारों में स्पष्टता आती है। व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक केंद्रित हो जाता है और धीरे-धीरे सफलता की दिशा में आगे बढ़ता है। यही कारण है कि विद्यार्थी, कलाकार, लेखक और व्यवसायी वर्ग के लोग भी मां कामाख्या की उपासना की ओर आकर्षित होते हैं।

मां कामाख्या की साधना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति में वृद्धि के रूप में देखा जाता है। 41 दिनों तक नियमित मंत्र जाप करने से व्यक्ति भीतर से मजबूत महसूस करने लगता है। भय, संदेह और हीनभावना जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं। व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ करने लगता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है, जहां साधक स्वयं को अधिक जागरूक और संतुलित अनुभव करता है।

तंत्र साधना के क्षेत्र में मां कामाख्या को विशेष रूप से सिद्धिदात्री माना गया है। उनके मंत्र जाप से साधक को तंत्र मार्ग में सफलता प्राप्त होती है और वह मां की दिव्य शक्तियों से जुड़ने लगता है। हालांकि यह मार्ग अत्यंत गंभीरता और शुद्ध भाव से अपनाने योग्य है, क्योंकि तंत्र साधना केवल इच्छापूर्ति का साधन नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान का मार्ग भी है। मां कामाख्या की कृपा से साधक को अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर मिलता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह मानी जाती है कि मां कामाख्या के मंत्र जाप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि मनोकामना पूर्ति केवल बाहरी इच्छाओं तक सीमित नहीं रहती। कई बार मां साधक को वही देती हैं, जो उसके लिए वास्तव में आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदलने लगता है और वह जीवन को अधिक सकारात्मक और संतुलित दृष्टि से देखने लगता है।

इस प्रकार मां कामाख्या की साधना केवल समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि जीवन के संपूर्ण रूपांतरण का मार्ग है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानता है, नकारात्मकता से मुक्त होता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। यही कारण है कि मां कामाख्या को केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली दिव्य चेतना माना गया है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब का शिलान्यास

▸▸ गृह मंत्री के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा राज्य सरकार संचालित देश का प्रथम 'बीएसएल-4' लैब

▸▸ गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

▸▸ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया की प्रेरक उपस्थिति

(जीएनएस)। गांधीनगर : केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के प्रथम अत्याधुनिक बायो-कंटेनमेंट फैसिलिटी 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' लैब तथा 'एनिमल बायो-सेफ्टी लेवल' सुविधा का गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में शिलान्यास किया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया भी उपस्थित रहे।

इस समारोह के दौरान गुजरात बायो-टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की 'बायो-सेफ्टी लेवल-4' सुविधा को भारत सरकार की 'बायोई3 नीति' अंतर्गत 'नेशनल सेंटर फॉर हाई कंटेनमेंट पैथोजन रिसर्च फैसिलिटी' के रूप में नियुक्त करने के लिए केन्द्रीय जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गुजरात के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आशय पत्र (एलओआई) प्रदान किया गया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की धरती से भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बायो-सेफ्टी क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। पुणे के बाद देश का यह केवल दूसरा उच्च स्तरीय लैब है, लेकिन राज्य सरकार की विशेष पहल से 362 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला यह देश का पहला बीएसएल-4 लैब बनेगा। भविष्य में यह लैब जानलेवा वायरसों से लड़ने के लिए भारत का अभेद्य सुरक्षा कवच तथा जैव-सुविधाओं का मजबूत किला सिद्ध होगा।

श्री शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ होना चाहिए'; विजन को दोहराते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह लैब शोधकर्ताओं तथा युवाओं के लिए अनेक अवसरों के द्वार खोलेगा। विशेषकर पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'वन हेल्थ मिशन' को इस लैब से गति मिलेगी। हाल ही में गुजरात द्वारा झेले गए चांदीपुरा तथा लम्पी स्किन डिसीज जैसे संकटों के विरुद्ध इस प्रकार की रिसर्च आधारित स्थायी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य थी।

भारत के बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आए क्रांतिकारी परिवर्तन के आँकड़े प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्ष में बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2014 में भारत की बायो-इकोनॉमी, जो 10 बिलियन डॉलर थी, वर्ष 2024 तक बढ़कर 166 बिलियन डॉलर के पार पहुँची है। अनुसंधान को आविष्कार की आत्मा मानते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली ढाँचागत सुविधाओं के कारण आज भारत के वैज्ञानिक अत्यंत सुरक्षित वातावरण में विश्व स्तरीय शोध-अनुसंधान कर रहे हैं।

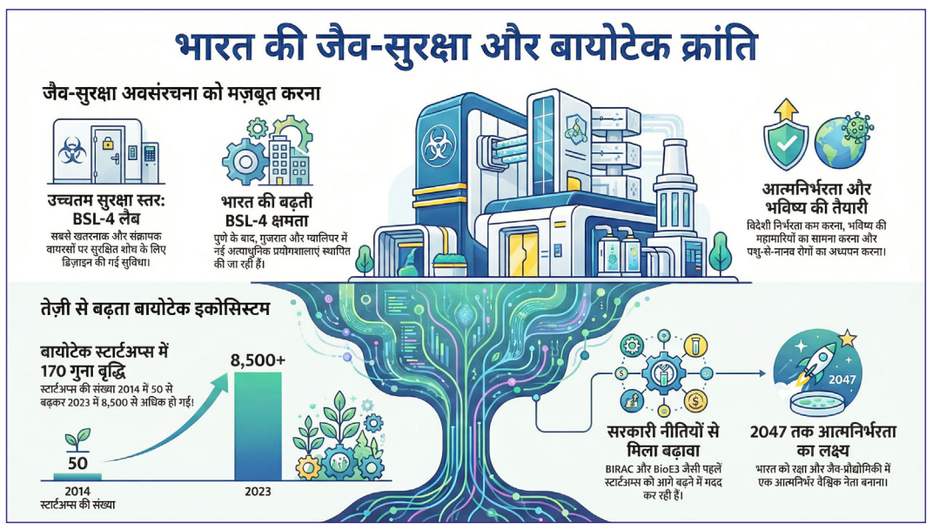

केन्द्रीय गृह मंत्री ने स्टार्टअप तथा निवेश क्षेत्र में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इस क्षेत्र में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जो आज 10,000 से अधिक हुए हैं। इसी प्रकार; इनक्यूबेटर्स की संख्या 6 से बढ़कर 95 और इनक्यूबेशन स्पेस 60 हजार स्क्वायर फीट से बढ़कर 9 लाख स्क्वायर फीट हुआ है। उल्लेखनीय रूप से; प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 7000 करोड़ रुपए तक पहुँचा है और पेटेंट फाइलिंग की संख्या भी 125 से बढ़कर 1300 को पार कर गई है, जो दर्शाता है कि भारत के युवा अब 'जॉब सीकर' नहीं, बल्कि 'जॉब गिवर' बने हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की 'बायोई3 नीति' अंतर्गत देश को बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अधिक ऊँचाई पर ले जाने का संकल्प है। भारत आज कोरोना तथा सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों की वैक्सीन का स्वदेशी निर्माण कर रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों तथा अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान किया कि भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। यह लैब आगामी समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम बनेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज 'विज्ञान' तथा 'विरासत'; दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने अल्प समय में वैक्सीन बनाकर 140 करोड़ नागरिकों को सुरक्षित करते हुए विश्व की सहायता की है, जिसकी नींव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राष्ट्र के विकास का आधार स्तंभ बनाने का दृष्टिकोण रहा है। इस लैब द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को अब सैंपल टेस्टिंग के लिए विदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को सिद्ध करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2027 तक सेमीकंडक्टर तथा बायो-टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर प्रथम पंक्ति में होगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने एंटीबायो-टिक दवाइयों के दुरुपयोग से उत्पन्न हो रहे 'साइलेंट डिजास्टर' (एएमआर) को लेकर चिंता व्यक्त की और विद्यार्थियों व शोधकर्ताओं का अनुसंधान द्वारा नई पीढ़ी को सुरक्षित करने का आह्वान किया। उन्होंने बायो-टेक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल फैसिलिटी का अधिकतम उपयोग कर मानव जीवन के लिए उपयोगी फार्मास्यूटिकल फॉर्मूलेशन और वैक्सीन विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह सुविधा केवल गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभरेगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जब देश 'विकसित भारत' की तरफ आगे बढ़ रहा है, तब बायो-टेक्नोलॉजी जैसा विज्ञान हमें सुरक्षा देगा और 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' जैसी विरासत हमें गौरवपूर्ण पहचान देगी। भारत आज संस्कृति की नींव पर आधुनिक विज्ञान की इमारत खड़ी कर रहा है। बायो-टेक क्षेत्र में हुआ यह नया अनुसंधान देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देश को संभावित महामारियों के विरुद्ध अधिक सुरक्षित बनाने वाले इस प्रकल्प को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हेल्थ केयर और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रकल्प बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समय से आगे सोचने वाले विजनरी लीडर हैं। उनके ऐसे ही विजन के कारण हमने गुजरात बायो-टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) को कार्यरत कर वायरल रोगों, जेनेटिक संक्रमणों और महामारी जैसे गंभीर स्वास्थ्य क्षेत्रों के निदान अनुसंधान के लिए बाहरी संस्थाओं पर निर्भर न रहकर आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री ने बीएसएल-4 लैब के कार्यरत होने से हाई रिस्क वाले वायरस पर राज्य में अनुसंधान संभव होने से समय पर, सटीक और विश्वसनीय निदान उपलब्ध होने तथा स्वास्थ्य प्रणाली के अधिक सशक्त और सज्ज बनने का विश्वास व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीआरसी केवल एक अनुसंधान संस्थान ही नहीं, बल्कि राज्य की बायो-टेक कैपेसिटी का नोडल सेंटर भी है। इसकी भूमिका देते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएल-4 लैब में होने वाला अनुसंधान सीधे निदान, उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में परिवर्तित होने वाला ट्रांजिशनल रिसर्च बनेगा।

उन्होंने कहा कि 'विकसित भारत@ 2047' के प्रधानमंत्री के संकल्प को स्वस्थ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के रूप में साकार करने में यह बीएसएल-4 फैसीलिटी माइलस्टोन सिद्ध होगी।

स्वागत भाषण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि जिस तरह भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने में महात्मा गांधी और सरदार पटेल का योगदान रहा है, उसी तरह आधुनिक भारत और गुजरात का भाग्य बदलने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है।

श्री मोढवाडिया ने कहा कि गुजरात की यह पहली और देश की अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान सुविधा वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में निर्णायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री की परिकल्पना से 'गुजरात स्टेट बायो-टेक्नोलॉजी मिशन' (जीएसबीटीएम) की स्थापना हुई थी। आज उसी विजन के परिणामस्वरूप गुजरात एशिया के प्रथम समर्पित बायो-टेक विश्वविद्यालय वाला राज्य बना है। जिस अनुसंधान सुविधा का आज शिलान्यास हुआ है, वह भारत सरकार द्वारा डेजिग्नेट गुजरात की इस प्रकार की पहली अनुसंधान सुविधा है।

इस अवसर पर गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, सांसद सर्वश्री हसमुखभाई पटेल, हरिभाई पटेल, मयंकभाई नायक, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, श्री अल्पेशभाई ठाकोर, भारत सरकार के बायो-टेक्नोलॉजी सचिव श्री राजेश गोखले, राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव श्री पी. भारती तथा गांधीनगर जिला कलेक्टर श्री मेहुल दवे सहित विभिन्न पदाधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

10 मिनट की डिलीवरी पर ब्रेक, क्विक कॉमर्स के बेलगाम मॉडल पर सरकार का सख्त संदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। क्विक कॉमर्स के नाम पर 10 मिनट में डिलीवरी देने की होड़ पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को देश के पारंपरिक व्यापार और डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार के इस फैसले का खुलकर स्वागत करते हुए इसे मानवता, सुरक्षा और व्यापारिक संतुलन की बड़ी जीत करार दिया है। कैट का कहना है कि लंबे समय से जिस खतरे की ओर वह सरकार और नीति निर्माताओं का ध्यान खींचता आ रहा था, आखिरकार उस पर ठोस कार्रवाई हुई है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि 10 मिनट की डिलीवरी का मॉडल दिखने में भले ही आधुनिक और उपभोक्ता हितैषी लगे, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई बेहद खतरनाक है। इस मॉडल में सबसे ज्यादा दबाव डिलीवरी कर्मियों पर पड़ता है, जिन्हें समय सीमा पूरी करने के लिए तेज रफ्तार, जोखिम भरे और कई बार जानलेवा हालात में काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डिलीवरी कर्मियों के साथ हुई दुर्घटनाओं और हादसों ने यह साफ कर दिया था कि यह व्यवस्था न तो टिकाऊ है और न ही मानवीय। खंडेलवाल ने बताया कि कैट ने इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संसद से लेकर सरकार के उच्च स्तर तक लगातार इसे उठाया। संसद

में उन्होंने डार्क स्टोर्स के अनियंत्रित विस्तार और 10 मिनट जैसी अव्यावहारिक समय-सीमा के दुष्परिणामों को विस्तार से रखा था। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्राचार और संवाद के जरिए यह चेतावनी दी जाती रही कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो इसके सामाजिक और आर्थिक परिणाम गंभीर होंगे। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनाया गया डार्क स्टोर मॉडल भी कैट की बड़ी चिंता रहा है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों में बने ये डार्क स्टोर्स न केवल शहरी नियोजन को बिगाड़ते हैं, बल्कि स्थानीय किराना दुकानों और छोटे व्यापारियों के लिए भी बड़ा खतरा बनते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी का दबाव इन डार्क स्टोर्स को शहर के हर कोने में फैलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे ट्रैफिक, सुरक्षा और शोर जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।

कैट का यह भी आरोप रहा है कि कई क्विक कॉमर्स कंपनियां मुनाफे की अंधी दौड़ में सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती हैं। डिलीवरी के दौरान होने वाले हादसों के बाद जिम्मेदारी तय करने के बजाय अक्सर प्लेटफॉर्म्स अपने सिस्टम और एल्गोरिद्म के पीछे छिप जाते हैं। खंडेलवाल ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल इंसानों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यापार मॉडल की सफलता का पैमाना केवल तेजी और मुनाफा नहीं, बल्कि सुरक्षा, न्याय और संतुलन भी होना चाहिए।

सरकार द्वारा 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगाए जाने को कैट ने एक साहसिक और दूरदर्शी फैसला बताया है। संगठन का मानना है कि यह कदम न केवल डिलीवरी कर्मियों की जान बचाने में मदद करेगा, बल्कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल भी बनाएगा। छोटे और मध्यम व्यापारी, जो अब तक तेज डिलीवरी के दबाव में पिछड़ते जा रहे थे, उन्हें भी इससे राहत मिलेगी।

हालांकि कैट का यह भी कहना है कि यह फैसला केवल शुरुआत है। डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स के तेजी से बदलते परिदृश्य में अभी कई संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। डार्क स्टोर्स के नियमन, डिलीवरी समय-सीमा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश, डिलीवरी कर्मियों के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अभी और काम किया जाना बाकी है। खंडेलवाल ने कहा कि अगर इन पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया, तो भविष्य में नए-नए रूपों में वही समस्याएं फिर सामने आ सकती हैं।

कैट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह डिजिटल व्यापार के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक संतुलित और जिम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम का समर्थक है। संगठन का मानना है कि तकनीक का इस्तेमाल उपभोक्ता सुविधा, व्यापारिक विकास और रोजगार सृजन के लिए होना चाहिए, न कि अराजकता और असुरक्षा के लिए। सरकार के इस कदम से यह संदेश गया है कि देश में व्यापार और तकनीक दोनों के लिए नियम और सीमाएं जरूरी हैं।

अंत में कैट ने भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में भी सरकार के साथ मिलकर काम करता रहेगा, ताकि एक ऐसी डिजिटल व्यापार व्यवस्था तैयार हो सके जो पारदर्शी, सुरक्षित और न्यायसंगत हो। 10 मिनट की डिलीवरी पर लगी रोक को कैट ने न केवल एक नीतिगत फैसला, बल्कि समाज के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का प्रतीक बताया है। उनका कहना है कि अगर समय पर यह ब्रेक नहीं लगाया जाता, तो तेज रफ्तार की यह दौड़ कई जिंदगियों को कुचल सकती थी। अब उम्मीद है कि क्विक कॉमर्स का भविष्य इंसानी जान और स्थानीय व्यापार दोनों के हितों को ध्यान में रखकर गढ़ा जाएगा।

डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

(जीएनएस)। ऑल इंडिया एससी/एसटी एसोसिएशन, इंजीनियरिंग एवं सिग्नल कारखाना शाखा द्वारा आयोजित डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कमर्शियल एवं ट्रैकमैन साबरमती टीमों के बीच खेला गया। फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रैकमैन साबरमती टीम विजेता बनी, जबकि कमर्शियल टीम उपविजेता रही। समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ श्री अशोक कुमार, Sr. DME वटवा एवं श्री एस.पी. गुप्ता, Sr. DME साबरमती भी उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दिनांक 11.01.2026 को साबरमती इंस्टिट्यूट में आयोजित इस टूर्नामेंट में ट्रैक मेंटेनर एवं कमर्शियल टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में कमर्शियल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 102 रन बनाए। टीम की ओर से श्री शिवकुमार प्रजापत ने शानदार अर्धशतक लगाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए ट्रैक मेंटेनर टीम ने मात्र 13.1 ओवर में जीत हासिल कर प्रतियोगिता अपने नाम की। कमर्शियल टीम उपविजेता रही।

कमर्शियल टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए ACM श्री हफीज खान पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के साथ उपस्थित रहे और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। यह प्रतियोगिता खेल भावना, टीमवर्क और सामाजिक समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण रही।

शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को भारत ने सिरे से नकारा संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होने का दोहराया संकल्प

(जीएनएस)। नई दिल्ली। शक्सगाम घाटी को लेकर चीन द्वारा दोहराए गए दावों पर भारत ने कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाते हुए उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है। भारत ने कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस पर चीन का कोई भी दावा न केवल निराधार है बल्कि अंतरराष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक तथ्यों के भी खिलाफ है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत ने चीन को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि बेबुनियाद नक्शों और बयानों के जरिए जमीनी हकीकत नहीं बदली जा सकती और भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। चीन की ओर से यह नया दावा ऐसे समय सामने आया है जब भारत ने हाल ही में शक्सगाम घाटी और आसपास के इलाकों में चीनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर चिंता जताई थी। भारत का कहना है कि ये परियोजनाएं अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में बनाई जा रही हैं और इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो रहा है बल्कि द्विपक्षीय संबंधों में भी तनाव बढ़ रहा है। इसके जवाब में चीन द्वारा अपने नक्शों में शक्सगाम घाटी को शामिल करना और उस पर दावा जताना भारत की नजर में एक उकसावे वाली कार्रवाई है। शक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील इलाका है। यह काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर तथा अक्साई चिन जैसे विवादित क्षेत्रों के निकट पड़ता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जम्मू-कश्मीर का हिस्सा रहा है और आज भी भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। हालांकि वर्तमान में यह इलाका पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन इससे भारत के दावे की वैधता कम नहीं होती। 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए तथाकथित सीमा समझौते को भारत ने शुरू से ही अवैध और अमान्य बताया है।

सोना-चांदी के वायदाओं में परस्पर विरुद्ध चाल: सोना वायदा 498 रुपये लुढ़का, चांदी वायदा 1210 रुपये तेज

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 231176.05 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 45165.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 186003.27 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 37648 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 2945.19 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 36563.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 141847 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142206 रुपये और नीचे में 141311 रुपये पर पहुंचकर, 142032 रुपये के पिछले बंद के सामने 498 रुपये या 0.35 फीसदी गिरकर 141534 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 286 रुपये या 0.25 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 115018 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 26 रुपये या 0.18 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 14395 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 141877 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142005 रुपये और नीचे में 141004 रुपये पर पहुंचकर, 378 रुपये या 0.27 फीसदी औंधकर 141370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 142399 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 142766 रुपये और नीचे में 141600 रुपये पर पहुंचकर, 142440 रुपये के पिछले बंद के सामने 364 रुपये या 0.26 फीसदी औंधकर 142076 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 269701 रुपये के भाव पर खूलकर, 272202 रुपये के दिन के उच्च और 266037 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 268970 रुपये के पिछले बंद के सामने 1210 रुपये या 0.45 फीसदी की मजबूती के साथ 270180 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1308 रुपये या 0.48 फीसदी की तेजी के संग 272043 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1267 रुपये या 0.47 फीसदी बढ़कर 272117 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

मेटल वर्ग में 5174.97 करोड़ रुपये के ट्रेड

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 45165.21 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 186003.27 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 36563.49 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37648 पॉइंट के स्तर पर

दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 6.2 रुपये या 0.47 फीसदी गिरकर 1309 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 70 पैसे या 0.22 फीसदी चढ़कर 313.4 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.45 रुपये या 0.46 फीसदी औंधकर 315.8 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 90 पैसे या 0.47 फीसदी की नरमी के साथ 192.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 3422.30 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5359 रुपये के भाव पर खूलकर, 5493 रुपये के दिन के उच्च और 5359 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 133 रुपये या 2.49 फीसदी की तेजी के संग 5468 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 134 रुपये या 2.51 फीसदी की तेजी के संग 5469 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 303.3 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 310.6 रुपये और नीचे में 298.6 रुपये पर पहुंचकर, 304.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.3 रुपये या 1.74 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 309.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 5.3 रुपये या 1.74 फीसदी की तेजी के संग 309.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा 995 रुपये पर खूलकर, 2.3 रुपये या 0.23 फीसदी औंधकर 979 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 14839.46 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21724.03 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 4343.29 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 358.80 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 30.63 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 431.35 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 1356.33 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2057.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.26 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19980 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 75467 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 24048 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 369370 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 41251 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 14425 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 37659 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 99116 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24321 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 47931 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 37500 पॉइंट पर खूलकर, 37849 के उच्च और 37300 के नीचले स्तर को छूकर, 36 पॉइंट घटकर 37648 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 58.9 रुपये की बढ़त के साथ 112.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 3.05 रुपये की बढ़त के साथ 17.25 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 144000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 181.5 रुपये की गिरावट के साथ 1489.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 268000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1120.5 रुपये की बढ़त के साथ 15524 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4.07 रुपये की गिरावट के साथ 42 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5 पैसे की नरमी के साथ 3.44 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 69 रुपये की गिरावट के साथ 49.5 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.8 रुपये की गिरावट के साथ 11.35 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 66 रुपये की बढ़त के साथ 198 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 230000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 67.5 रुपये की गिरावट के साथ 1704.5 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.94 रुपये की बढ़त के साथ 33.2 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 35 पैसे की नरमी के साथ 1.4 रुपये हुआ।

करुणा अभियान - 2026

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने करुणा अभियान के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का दौरा किया

उत्तरायण में पतंग-डोर से घायल होने वाले पक्षियों को बचाने और उनके उपचार के लिए पूरे राज्य में लगभग 728 वेटरनरी चिकित्सक, 8620 सेवाभावी स्वयंसेवक सेवारत, राज्य भर में 1036 उपचार केंद्र और कलेक्शन सेंटर बनाए गए

पक्षी उपचार केंद्रों की जानकारी 8320002000 नंबर पर वॉट्सऐप द्वारा और वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है

2017 से शुरू हुए करुणा अभियान के तहत कुल 1.12 लाख पशु-पक्षियों का रेस्क्यू हुआ

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर पक्षियों को घायल होने से बचाने और घायल पक्षियों के उपचार के लिए चल रहे राज्यव्यापी करुणा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया के साथ अहमदाबाद के बोड़कदेव क्षेत्र में कार्यरत वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया और वाटर बर्ड्स सेंटर का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख डॉ. ए.पी. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तरायण पर्व में घायल पक्षियों को बचाने का यह अभूतपूर्व अभियान है। इस अभियान में अब तक हजारों घायल पक्षियों की जान बचाई गई है। 10 से 20 जनवरी के दौरान चलने वाले इस अभियान को सफल बनाने के लिए पशुपालन विभाग, वन विभाग, महानगर पालिकाएं और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थान सहभागी बने हैं।

करुणा अभियान-2026 के अंतर्गत लगभग 728 से अधिक वेटरनरी चिकित्सक और 8620 से अधिक सेवाभावी स्वयंसेवक सेवारत हैं। पूरे राज्य में कुल 1036 से अधिक उपचार केंद्र और कलेक्शन सेंटर भी बनाए गए हैं। इस अभियान के दौरान राज्यभर में पशु क्लीनिक, वेटरनरी पॉलिक्लीनिक और शाखा पशु क्लीनिकों के अलावा मोबाइल पशु क्लीनिक और करुणा एनीमल एंबुलेंस छुट्टी के दिन भी कार्यरत रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 से शुरू की गई इस करुणामय पहल के चलते अनेक मूक पशु-पक्षियों को नवजीवन मिला है। उत्तरायण जैसे त्योहारों और लोकोत्सवों के दौरान बेजुबान जीवों की चिंता कर उनके उपचार और देखभाल का यह करुणा अभियान गुजरात की अनूठी पहल बन गया है।

गत वर्ष करुणा अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 12,771 से अधिक पशु-पक्षियों को रेस्क्यू किया गया था, जबकि पिछले 9 वर्षों में इस अभियान के तहत राज्य भर में 1,12,951 पशु-पक्षियों को रेस्क्यू किया है। जिनमें से 1,03,874 पशु-पक्षियों को उचित उपचार प्रदान कर बचा लिया गया।

गुजरात द्वारा सर्वप्रथम शुरू किए गए 'करुणा अभियान' का आदर्श मॉडल आज पूरे देश के लिए पथप्रदर्शक बन गया है।

उत्तरायण पर्व के दौरान पतंग की डोर से कोई बेजुबान पशु या पक्षी घायल न हो, इस बात की सतर्कता के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरणा और मार्गदर्शन में 10 से 20 जनवरी के दौरान राज्यव्यापी करुणा अभियान चलाया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य के किसी भी स्थल पर घायल पक्षियों को त्वरित और उचित उपचार प्रदान करने के लिए वन विभाग द्वारा वॉट्सऐप नंबर 8320002000 और हेल्पलाइन नंबर 1926 जारी किया गया है, जो चौबीसों घंटे सातों दिन कार्यरत रहेगा। इस वॉट्सऐप नंबर पर 'Hi' मेसेज मेसेज भेजने पर एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करने से जिलेवार उपलब्ध सभी पक्षी उपचार केंद्रों की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके अलावा, पशुपालन विभाग का 1962 नंबर भी सेवारत है। नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर मूक पशु-पक्षियों की जान बचा सकते हैं।

मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचनबेन, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांग दाणी, राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, पशुपालन विभाग के निदेशक सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी, करुणा अभियान से जुड़े विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवक और एनसीसी के कैडेट्स उपस्थित रहे।

रेल प्रशासन द्वारा जनता से पटरियों के ऊपर लगे हाई वोल्टेज तारों से सावधान रहने की अपील

(जीएनएस)। रेल प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भावनगर रेलवे मंडल के सभी खंडों में रेलवे लाइनों के ऊपर 25,000 वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक (OHE) तारें लगी हुई हैं, जो अत्यंत खतरनाक हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखने में आया है कि पतंग उड़ाने के दौरान धागे (डोर) 25,000 वोल्ट की ओएचई तारों में उलझ जाते हैं। इससे रेल कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न हो जाता है। ट्रैक पर कार्यरत कर्मचारियों को विशेष सावधानी बरतने तथा किसी भी स्थिति में पतंग के धागों के संपर्क में न आने की अपील की गई है, क्योंकि इससे विद्युत करंट लगने का गंभीर खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया है कि जनसाधारण रेलवे ट्रैक के समीप पतंग उड़ाते हैं और ओएचई तारों से फंसी पतंग निकालने का प्रयास करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे रेलवे पटरी के पास पतंग उड़ाने से बचें तथा रेलवे के हाई वोल्टेज ट्रैक्शन तारों से किसी भी वस्तु को निकालने का प्रयास न करें। उन्होंने सामाजिक हित में इस महत्वपूर्ण संरक्षा संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की भी अपील की है।

रेल प्रशासन जनता की संरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सहयोग की अपेक्षा करता है।

अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे परिसर में थूकने एवं गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

12 जनवरी को 158 लोगों पर कार्रवाई, 23,950 का जुर्माना वसूला गया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा रेलवे परिसर में स्वच्छता बनाए रखने तथा यात्रियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 198 एवं 167 के अंतर्गत 12 जनवरी 2026 को एक विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया।

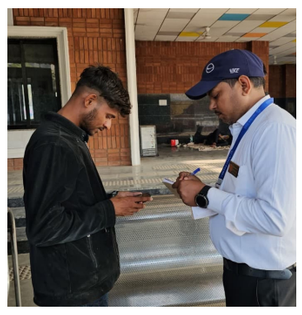

इस अभियान के दौरान अहमदाबाद मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में कुल 158 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनसे 23,950 का जुर्माना वसूला गया।

स्टेशन-वार विवरण इस प्रकार है—

- अहमदाबाद स्टेशनः 69 मामलों में 11,800
- साबरमतीः 13 मामलों में 1,400
- महेसाणाः 5 मामलों में 1,000
- पालनपुरः 17 मामलों में 2,500
- विरमगामः 6 मामलों में 750
- गांधीधामः 18 मामलों में 3,100

इसके अतिरिक्त Sr DCM SQD द्वारा 30 मामलों में 3,400 का जुर्माना लगाया गया। इस संपूर्ण अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर कुल 22 रेल कर्मचारियों की तैनाती कर सघन निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

रेल प्रशासन यात्रियों एवं आम जनता से अपील करता है कि रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में थूकने एवं गंदगी फैलाने से परहेज करें तथा स्वच्छता से संबंधित नियमों का पालन करें।

स्वच्छ रेलवे, सुरक्षित रेलवे के निर्माण में सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

एक मैसेज, टूटा हुआ दिल और मौत का फैसला: डेढ़ महीने बाद सामने आई प्रेम और पीड़ा की कहानी

(जीएनएस)। जालौर। राजस्थान के जालौर जिले से सामने आई यह घटना केवल एक आत्महत्या की खबर नहीं, बल्कि उस मानसिक पीड़ा की दास्तान है, जो चुपचाप किसी युवा को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। 21 साल के सुरेश कुमार मेघवाल की मौत को पहले एक सामान्य आत्महत्या मानकर मामला बंद कर दिया गया था, लेकिन डेढ़ महीने बाद एक अलमारी में मिले सुसाइड नोट ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। अब इस मामले में सुरेश के पिता ने बेटे की प्रेमिका पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है।

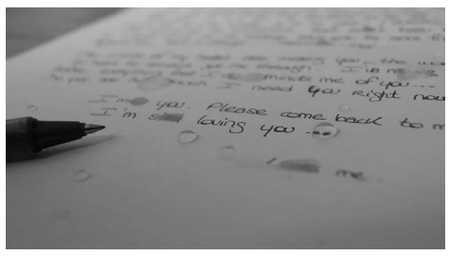

पिता घर की अलमारी में कुछ सामान रख रहे थे, तभी एक कागज उनके हाथ लगा। यह वही कागज था, जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। वह सुरेश का लिखा हुआ सुसाइड नोट था। नोट पढ़ते ही पिता की आंखों से आंसू बह निकले और उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा किस मानसिक तूफान से गुजर रहा था।

सुसाइड नोट में सुरेश ने अपनी प्रेमिका को अपना पहला और आखिरी प्यार बताया था। उसने लिखा था कि वह उसे अपनी पत्नी मान चुका था और उसके साथ पूरी जिंदगी के सपने देख रहा था। नोट में यह भी दर्ज था कि प्रेमिका से बात न होने पर वह रात-रात भर सो नहीं पाता, अकेले बैठकर रोता रहता था और खुद को असहाय महसूस करता था। अंत में उसने लिखा, "कोई बात नहीं मेरी जान अब मैं अलविदा कह रहा हूं। गुड-बाय माय लव।"

मामला आहोर थाना क्षेत्र के गोदन गांव का है। 29 नवंबर 2025 को सुरेश का शव घर के कमरे में पंखे से लटका मिला था। सुबह जब परिजनों ने दरवाजा खोला तो यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस को सूचना दी गई, शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम कराया गया और प्रारंभिक जांच के बाद इसे आत्महत्या मानते हुए केस बंद कर दिया गया। उस समय न कोई सुसाइड नोट मिला और न ही किसी तरह का संदेह सामने आया।

समय बीतता गया, लेकिन परिवार के लिए सुरेश की कमी और सवाल जस के तस बने रहे। करीब डेढ़ महीने बाद जब सुरेश के इस नोट के मिलने के बाद सुरेश के पिता ने पूरे घटनाक्रम को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि जिस युवती से सुरेश प्यार करता था, वह रिश्तेदारी में आती थी, इसलिए दोनों की शादी संभव नहीं थी। दोनों परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे और कई बार सुरेश को समझाया गया था। यहां तक कि सुरेश की मां खुद युवती के घर जाकर उसे बेटे से संपर्क न करने की गुहार लगा चुकी थीं। परिजनों का आरोप है कि इसके बावजूद युवती लगातार सुरेश को मैसेज करती रही। सुरेश भावनात्मक रूप से उससे गहराई से जुड़ा हुआ था और हर मैसेज का उस पर गहरा असर पड़ता था। पिता के अनुसार, एक दिन युवती ने सुरेश को मोबाइल पर जहर की शीशी की फोटो भेजी। इसके साथ लिखा गया मैसेज था—"बाय-बाय डिकु, खुश रहना। मैं बहुत परेशान करती हूं ना। अब आपको जो ठीक लगे, वह कर लेना। जब मैं ही नहीं रहूंगी" यह मैसेज पढ़कर सुरेश पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि उसकी प्रेमिका आत्महत्या करने जा रही है। वह घबराया, डर गया और खुद को पूरी तरह दोषी मानने लगा। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक दबाव और सदमे में आकर सुरेश ने खुद फंदा लगाकर जान दे दी। अब, डेढ़ महीने बाद सामने आए इस सुसाइड नोट और मोबाइल मैसेज के आधार पर सुरेश के पिता ने आहोर थाने में युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मोबाइल चैट, कॉल डिटेल्स तथा अन्य डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है।

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि भावनात्मक संबंधों में असंतुलन और मानसिक दबाव किस हद तक किसी युवा को आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है। एक तरफ प्रेम, उम्मीद और भविष्य के सपने, दूसरी तरफ सामाजिक बंदिशें और रिश्तों की मजबूरियां—इनके बीच फंसा सुरेश आखिरकार टूट गया।

गोदन गांव में आज भी यह घटना लोगों के दिलों में सन्नाटा पैदा कर देती है। सुरेश के माता-पिता बेटे की तस्वीर को देखकर यही कहते हैं कि काश समय रहते उसके मन की पीड़ा समझ पाते। यह कहानी सिर्फ एक युवक की मौत की नहीं, बल्कि उस खामोश दर्द की है, जो अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर जिंदगी छीन लेता है।

इज्जतनगर मंडल ने तोड़ा रिकॉर्ड: तीसरी तिमाही में 5.29 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, आय में भी बढ़ोतरी

(जीएनएस)। बरेली। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में यात्री और राजस्व दोनों ही क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। मंडल से तीसरी तिमाही में यात्रा करने वालों की संख्या 5.29 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है। यह आंकड़ा न केवल यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को दर्शाता है, बल्कि रेलवे की सेवा में लोगों की बढ़ती संतुष्टि का भी संकेत है।

यात्रियों की संख्या में इजाफे के साथ आय में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दर्ज की गई। यात्रियों से प्राप्त राजस्व 274 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो बीते साल के मुकाबले करीब 4 प्रतिशत अधिक है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और बेहतर वाणिज्यिक प्रबंधन ने मंडल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा ढुलाई सेवाओं, माल लोडिंग और अन्य कोचिंग गतिविधियों के माध्यम से भी मंडल को अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। विशेष रूप से वाणिज्य सन्ड्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई, जो मंडल के व्यापारिक संचालन की सफलता को दर्शाती है। दिसंबर माह में काठगोदाम स्टेशन पर बड़े पार्किंग अनुबंध और अन्य स्थानों पर पार्किंग से हुई रिकॉर्ड मासिक आय ने कुल सकल आय में भी वृद्धि की। कुल मिलाकर मंडल की सकल आय 434 करोड़ रुपये से अधिक रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 4 प्रतिशत अधिक है।

मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा ने इस उपलब्धि को मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष के शेष समय में भी इसी गति के साथ काम करते हुए और बेहतर परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यात्रियों की संतुष्टि, समय पर ट्रेनों के संचालन और वाणिज्यिक गतिविधियों में निरंतर सुधार पर जोर दिया।

वीणा सिन्हा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मंडल ने प्लेटफॉर्म, टिकटिंग और पार्किंग सेवाओं के साथ-साथ कोचिंग और माल ढुलाई में भी आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाया, जिससे संचालन में तेजी और पारदर्शिता आई है। इसके अलावा, मंडल ने तकनीकी उन्नयन, डिजिटल टिकटिंग और यात्रियों की शिकायत निवारण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है, जिससे रेलवे सेवा में दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है।

पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि इज्जतनगर मंडल का यह प्रदर्शन पूरे मंडल के लिए प्रेरणादायक है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और आय में सुधार यह संकेत देते हैं कि मंडल ने न केवल यात्री सेवाओं में सुधार किया है, बल्कि वाणिज्यिक दृष्टिकोण से भी मजबूत स्थिति हासिल की है। यह सफलता आने वाले वर्षों में मंडल को और ऊंचाईयों तक पहुंचाने में मदद करेगी और रेलवे को क्षेत्र में आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने में अहम योगदान देगी।

इस उपलब्धि से यह स्पष्ट होता है कि इज्जतनगर मंडल ने न केवल यात्री संतुष्टि में सुधार किया है, बल्कि आय के हर स्रोत को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित कर वित्तीय मजबूती भी हासिल की है। मंडल की इस प्रगति को रेलवे मंत्रालय ने भी सराहा है और इसे पूरे पूर्वोत्तर रेलवे के लिए एक आदर्श मॉडल बताया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के प्रकाश मनोदिव्यांग स्कूल का दौरा किया

मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवेदना और परिवार के बड़े-बुजुर्ग की तरह वात्सल्य व स्नेह भाव से स्कूल के बच्चों को मिठाई बांटकर उन्हें उत्तरायण की शुभकामनाएं दीं

मनोदिव्यांग बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति

मुख्यमंत्री ने अमेरिका की यूनिफाइड बास्केटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक सहित स्पेशल खेल महाकुंभ के विजेता बच्चों को सम्मानित किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के बोड़कदेव क्षेत्र में स्थित प्रकाश मनोदिव्यांग निवासी शाला का दौरा किया और स्कूल की विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने मनोदिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षण देने के कार्य की तुलना उत्तम सेवा के साथ की। मुख्यमंत्री उत्तरायण से पूर्व मंगलवार सुबह बोड़कदेव स्थित इस मनोदिव्यांग स्कूल में पहुंचे। उन्होंने परिवार के किसी बड़े-बुजुर्ग की तरह वात्सल्य व स्नेह भाव से मनोदिव्यांग बच्चों को मिठाई वितरित कर उन्हें उत्तरायण पर्व की शुभकामनाएं दीं। मनोदिव्यांग बच्चों ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने संस्था के कार्यों की भी सराहना की, जिसके अंतर्गत मनोदिव्यांग बच्चों को दैनिक और सामाजिक जीवन के कार्यों को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

संस्था की ट्रस्टी डॉ. सुजाताबेन शाह ने संस्था की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि संस्था की स्थापना से लेकर अब तक कुल 1500 से अधिक बच्चों ने इस स्कूल में पढ़ाई की है। वर्तमान में लगभग 100 बच्चों को अक्षरों, रंगों और आकृतियों को पहचानने के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गत महीने अमेरिका के प्यूर्टो रिको में आयोजित यूनिफाइड ओलंपिक बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्कूल के हित सावंत नाम के विद्यार्थी ने कांस्य पदक जीता है। जबकि, कुल 27 विद्यार्थियों ने जिला और राज्य स्तर पर स्पेशल खेल महाकुंभ में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले विद्यार्थियों का सम्मान भी किया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने नाट्य प्रस्तुति भी दी।

इस दौरान उप महापौर श्री जतिनभाई पटेल, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री देवांगभाई दाणी सहित गणमान्य लोग और संस्था के न्यासी, शिक्षक आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत – गुजरात यात्रा संपन्न

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने दी भावपूर्ण विदाई

(जीएनएस)। गांधीनगर : फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की भारत- गुजरात यात्रा मंगलवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। श्री मर्ज ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रणनीतिक कार्यक्रमों में तथा भारत-जर्मन सीईओ फोरम में सहभागिता करने के बाद मंगलवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे से जर्मनी के लिए प्रस्थान किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित महानुभावों ने जर्मन चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज को भावपूर्ण विदाई दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, शहर पुलिस आयुक्त श्री जी. एस. मलिक, मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी श्री ज्वलंत त्रिवेदी, जिला कलेक्टर सुजीत कुमार, विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

करूर त्रासदी की परछाइयाँ दिल्ली तक: भगदड़ मामले में एक्टर विजय से फिर पूछताछ, सियासी और कानूनी दबाव तेज

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में हुई भीषण भगदड़ की घटना एक बार फिर सुर्खियों में है और इस मामले में टीवीके प्रमुख व मशहूर अभिनेता विजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने इस मामले की जांच के सिलसिले में विजय को 19 जनवरी को दोबारा दिल्ली बुलाया है। इससे पहले भी उनसे लंबी पूछताछ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, करीब छह घंटे तक चली पिछली पूछताछ में सीबीआई ने रैली के आयोजन, भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और कार्यक्रम से जुड़े निर्णयों को लेकर विस्तार से सवाल किए थे। यह भगदड़ 27 सितंबर को करूर में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान हुई थी, जहां हजारों की संख्या में लोग विजय को देखने और सुनने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान अचानक हालात बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआती दौर में इस मामले की जांच को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और अलग-अलग एजेंसियों को जांच सौंपी गई, लेकिन संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आ सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय आयोग को रद्द करते हुए जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा की जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव की गुंजाइश न रहे। इसके बाद से ही सीबीआई ने मामले की परत-दर-परत जांच शुरू की है।

सीबीआई की जांच का फोकस मुख्य रूप से इस बात पर है कि कार्यक्रम के आयोजन में किस स्तर पर चूक हुई, भीड़ नियंत्रण के लिए क्या इंतजाम किए गए थे और आयोजन से जुड़े लोगों ने सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीरता दिखाई थी। जांच एजेंसी यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या रैली के आयोजन में तय मानकों और नियमों का पालन किया गया था या नहीं। इसी कड़ी में विजय से बार-बार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कार्यक्रम का सीधा संबंध उनकी पार्टी और उनके सार्वजनिक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था।

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी हादसे के कारणों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी। तमिलनाडु पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया था कि कार्यक्रम स्थल पर विजय के पहुंचने में कथित तौर पर काफी देरी हुई, जिससे वहां मौजूद भीड़ में नाराजगी फैल गई और हालात बेकाबू हो गए। पुलिस का यह भी कहना था कि पर्याप्त सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं थे, जिसके चलते भगदड़ की स्थिति बनी। हालांकि इन आरोपों को विजय ने सिरे से खारिज करते हुए इसे सत्ताधारी डीएमके की साजिश करार दिया था। डीएमके ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

अब जब मामला सीबीआई के हाथ में है, तो जांच की दिशा और तेज हो गई है। सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि कार्यक्रम के आयोजन से पहले प्रशासन से किस तरह की अनुमति ली गई थी, सुरक्षा एजेंसियों के साथ क्या समन्वय था और आयोजकों की ओर से किन निर्देशों का पालन किया गया। 19 जनवरी को होने वाली अगली पूछताछ को इस मामले में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हुई पूछताछ के आधार पर एजेंसी कई नए सवालों और दस्तावेजों के साथ विजय से दोबारा जवाब तलब कर रही है।

करूर भगदड़ की जांच अब सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं रह गई है, बल्कि यह राजनीतिक जवाबदेही, सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन जैसे बड़े मुद्दों से भी जुड़ गई है। 41 लोगों की मौत ने इस त्रासदी को और भी संवेदनशील बना दिया है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं सीबीआई की कार्रवाई और विजय से बार-बार पूछताछ यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।